क्या उपभोग असमानता घट रही है? - 2022-23 का एनएसएसओ सर्वेक्षण हमें क्या बताता है

कौस्तुभ, सतद्रु दास,
पवन गोपालकृष्णन, और
देबोज्योति मजूमदार^

यह आलेख विभिन्न समूहों के बीच घरेलू उपभोग व्यय में अभिसरण या विचलन का विश्लेषण करके भारत में उपभोग असमानता का आकलन करता है। इसके अलावा, लेख रंगराजन समिति की गरीबी रेखा को अद्यतन करते हुए राज्यों में गरीबी की घटनाओं का अनुमान लगाता है। अध्ययन में पाया गया है कि परिवारों के बीच उपभोग व्यय में अभिसरण की एक व्यापक प्रवृत्ति है, लेकिन कुछ उल्लेखनीय अपवाद भी हैं। भारत के राज्यों में गरीबी की घटनाओं में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।

परिचय

हाल के वर्षों में, भारत ने उपभोग वृद्धि में मंदी का अनुभव किया है, जो आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों वाला एक रुझान है। उपभोग जो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है न केवल समग्र मांग को दर्शाता है, बल्कि परिवारों के जीवन स्तर और कल्याण को भी दर्शाता है। उपभोग असमानता और क्षेत्रीय अभिसरण का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां उपभोग में असमानताएँ आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कायम रख सकती हैं, वहां अभिसरण अधिक समावेशी विकास की दिशा में प्रगति का संकेत दे सकता है। जबकि वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के रुझान पिछले एक दशक में राज्यों के बीच बढ़ती असमानता दर्शाते हैं (कौस्तुभ और घोष, 2023; 2025), यह जांचना आवश्यक हो जाता है कि यह उपभोग के संदर्भ में कैसे साकार हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाता है: क्या बढ़ती स्थानिक आय असमानता उपभोग असमानता में भी इसी अनुपात में वृद्धि का कारण बन रही है? पिछले दशक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी की तरह के अप्रत्याशित झटकों जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों का असमानता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। जहाँ कुछ विश्लेषकों ने अन्य स्रोतों से प्राप्त वास्तविक साक्ष्यों और आंकड़ों का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि इन घटनाओं ने बढ़ती असमानता में योगदान दिया (हिमांशु, 2017; झा और लाहोटी, 2022; घोष, 2024), वहीं अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि इन घटनाओं के प्रभाव या तो अस्थायी थे या असमानता के कारण बने (चंदा और कुक, 2022; गुप्ता और अन्य., 2021)। राज्यों में श्रम गतिशीलता में वृद्धि और सु-लक्षित नीतिगत उपाय उपभोग पर बढ़ती आय असमानता के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।

विपरीत निष्कर्षों और परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2022-23 का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण इन मुद्दों की विस्तार से जांच करने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा ग्यारह वर्षों के अंतराल के बाद, जुलाई 2024 में जारी किया गया था। 2.6 लाख परिवारों को शामिल करते हुए, यह डेटासेट आय समूहों, राज्यों और ग्रामीण-शहरी विभाजनों में उपभोग व्यवहारों की गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे असमानता के चालकों और क्षेत्रीय अभिसरण की सीमा का व्यापक विश्लेषण संभव हो पाता है। इन रुझानों को समझना भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और समान आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए उपभोग असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। इन गतिशीलताओं की जांच करके, इस अध्ययन का उद्देश्य नीतिगत हस्तक्षेपों को सूचित करना है जो संतुलित विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास के लाभ आबादी में अधिक समान रूप से वितरित किए जाएं।

एचसीईएस 2022-23 के संबंध में मीडिया और अकादमिक अनुसंधान में अधिकांश चर्चा सर्वेक्षण से प्राप्त समग्र आंकड़ों

^ लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

पर केंद्रित रही है। इन लेखों ने 2011-12 और 2022-23 के सर्वेक्षणों की तुलना करके भारतीय अर्थव्यवस्था के उपभोग पैटर्न में उभरते प्रमुख रुझानों का विश्लेषण किया है। इन लेखों के निष्कर्षों को मोटे तौर पर संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: 2011-12 और 2022-23 के बीच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) में वृद्धि हुई है; उपभोग में ग्रामीण और शहरी अंतर में कमी आई है; कुल उपभोग व्यय में भोजन की हिस्सेदारी में गिरावट आई है; और अंत में, आय के विभिन्न दशमलवों में उपभोग असमानता में कमी आई है (रामपाल, 2024; अय्यर, 2024; नागेश्वरन और अन्य., 2024)।

पिछले अध्ययनों में खाद्य पदार्थों की तुलना में गैर-खाद्य पदार्थों के उपभोग में अधिक स्थानिक असमानता पाई गई है और एचसीईएस 2022-23 के आधार पर एमपीसीई के संदर्भ में राज्यों के बीच ग्रामीण एमपीसीई में स्थानिक असमानता शहरी एमपीसीई से अधिक है (मित्रा और श्रीवास्तव, 2024)। इसी तरह, बोनू, 2024 ने सामाजिक समूहों के बीच उपभोग असमानता का विश्लेषण किया। यह पाया गया कि ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियाँ उपभोग पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर हैं। मोटे तौर पर, उन्होंने इस बात के प्रमाण दिए कि अनुसूचित जनजातियाँ उपभोक्ता पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर हैं और उसके बाद लगभग सभी राज्यों में अनुसूचित जातियाँ हैं। इन अध्ययनों ने उपभोग असमानताओं के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करने के लिए केवल एचसीईएस 2022-23 पर ध्यान केंद्रित किया।

वर्तमान लेख एचसीईएस 2022-23 के माइक्रो-डेटा का विश्लेषण करके और एनएसएसओ उपभोग सर्वेक्षणों के पिछले दौर के साथ उनकी तुलना करके उपभोग व्यय में स्थानिक और अस्थायी भिन्नता के रुझानों का विश्लेषण करके इस चर्चा में योगदान देता है।

एनएसएसओ सर्वेक्षण दौर 2011-12 और 2022-23 के तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से, अध्ययन में शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच, उच्च उपभोग और निम्न उपभोग वाले परिवारों के बीच, और राज्यों में कई आयामों में व्यय असमानता में कमी पाई गई है। उपभोग असमानता में यह कमी गरीबी के स्तर पर भी प्रभाव डाल सकती है। इसका पता लगाने के लिए, वर्ष 2014 में रंगराजन समिति द्वारा अनुशंसित उपभोग व्यय आधारित गरीबी रेखा को वर्तमान कीमतों के अनुसार उचित रूप से समायोजित करके गरीबी के भार का अनुमान लगाया गया है। इन अनुमानों के परिणाम राज्यों में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाते हैं।

लेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है: खंड II व्यय वर्गों में उपभोग व्यय में भिन्नता का विश्लेषण करता है, खंड III शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच भिन्नता प्रस्तुत करता है, जबकि खंड IV राज्यों में भिन्नता की जांच करता है। खंड V बड़े राज्यों के लिए रंगराजन समिति की गरीबी रेखा को अद्यतन करता है और गरीबी की घटनाओं की गणना करता है। अंत में, खंड VI कुछ नीति अंतर्दृष्टि प्रदान करके समाप्त होता है।

II. व्यय वर्गों में अभिसरण

व्यय वर्गों में असमानता का विश्लेषण करने के लिए, प्रत्येक व्यय वर्ग के औसत व्यय और संपूर्ण नमूने के माध्यिका व्यय के बीच के अनुपात की गणना की जाती है। यह अभ्यास शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए अलग-अलग किया जाता है[1]। अभिसरण के लिए, 2011-12 और 2022-23 के बीच माध्यिका से नीचे के फ्रैक्टाइल के लिए अनुपात में वृद्धि और माध्यिका से ऊपर के फ्रैक्टाइल के लिए कमी होनी चाहिए।

यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में, माध्यिका से नीचे के अधिकांश फ्रैक्टाइल के लिए अनुपात में वृद्धि हुई और माध्यिका से ऊपर के अधिकांश फ्रैक्टाइल के लिए कमी आई (चार्ट 1)।

[1] असमानता को शीर्ष फ्रैक्टाइल और निचले फ्रैक्टाइल के औसत एमपीसीई के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। चार्ट में, प्रत्येक क्वांटाइल के औसत एमपीसीई और माध्यिका एमपीसीई के बीच के अनुपात को बार के रूप में दर्शाया गया है। यह अनुपात 50 से नीचे के क्वांटाइल के लिए 1 से कम और 50 से ऊपर के क्वांटाइल के लिए 1 से अधिक होगा। 50 से नीचे के फ्रैक्टाइल के अनुपात में वृद्धि का अर्थ माध्यिका की ओर गति होगा और 50 से ऊपर के फ्रैक्टाइल के अनुपात में गिरावट का अर्थ भी माध्यिका की ओर गति होगा, इसलिए, असमानता में कमी का संकेत होगा।

चार्ट 1: शहरी असमानता माप: 2011-12 बनाम 2022-23

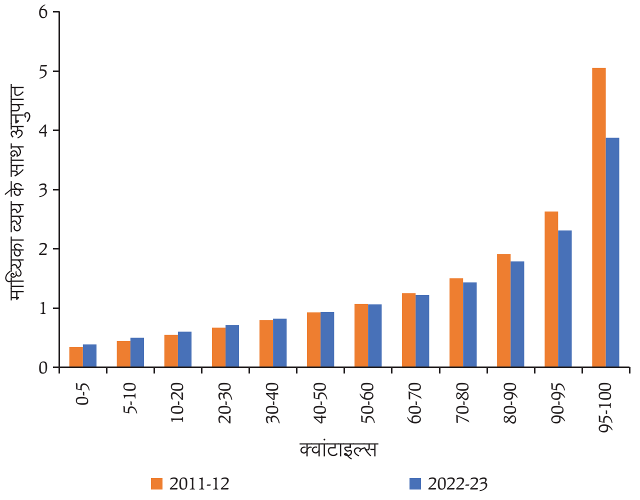

नोट: क्षैतिज अक्ष में क्वांटाइल्स के संदर्भ में व्यय वर्ग शामिल हैं।
स्रोत: एनएसएसओ 2011-12 और 2022-23; तथा लेखकों के अनुमान।

ग्रामीण क्षेत्रों में, माध्यिका से नीचे के अधिकांश फ्रैक्टाइल के लिए अनुपात अपरिवर्तित रहा है, लेकिन शीर्ष चार अंशों के लिए इसमें कमी आई है (चार्ट 2)। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2011-12 की तुलना में शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए व्यय वर्गों में असमानता में कमी आई है, हालाँकि शहरी क्षेत्रों में गिरावट अधिक रही है।

III. शहरी और ग्रामीण परिवारों के बीच अभिसरण

शहरी-ग्रामीण अंतर को शहरी प्रीमियम का उपयोग करके मापा जाता है, जिसे वास्तविक शहरी एमपीसीई और वास्तविक ग्रामीण एमपीसीई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। वास्तविक मूल्यों की गणना शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए उनके संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सीपीआई) के साथ नाममात्र एमपीसीई को घटाकर की जाती है ताकि सभी मूल्यों को 2011-12 की कीमतों के संदर्भ में व्यक्त किया जा सके। 2009-10 में अपने चरम पर पहुँचने के बाद से इस अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो दर्शाती है कि उपभोग के संदर्भ में शहरी-ग्रामीण अंतर 2009-10 से लगातार घट रहा है (चार्ट 3)।

हालाँकि, आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि शहरी प्रीमियम में गिरावट व्यय वर्गों में एक समान नहीं है। विशेष रूप से,

चार्ट 2: ग्रामीण असमानता माप 2011-12 बनाम 2022-23

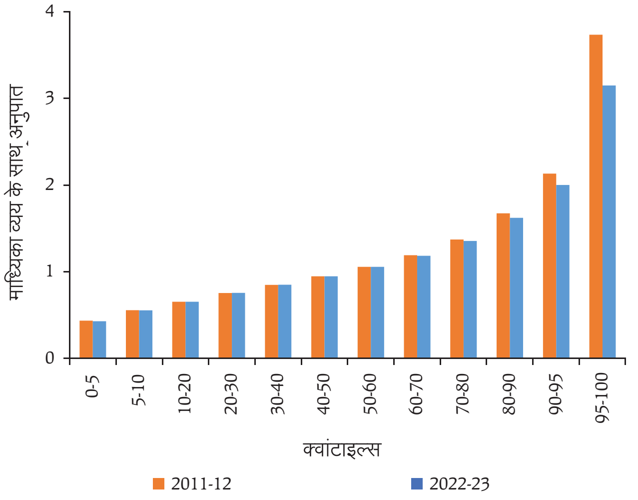

नोट: क्षैतिज अक्ष में क्वांटाइल्स के संदर्भ में व्यय वर्ग शामिल हैं।
स्रोत: एनएसएसओ 2011-12 और 2022-23; तथा लेखकों के अनुमान।

शहरी प्रीमियम निचले 30 प्रतिशत में बढ़ा है और उपभोग के शीर्ष 70 प्रतिशत वर्गों में घटा है (चार्ट 4)। इसका अर्थ है कि बेहतर स्थिति वाले परिवारों के लिए शहरी-ग्रामीण अंतर कम हुआ है, लेकिन गरीब परिवारों के लिए बढ़ा है।

इसके बाद, अनुमानित शहरी प्रीमियम की तुलना राज्यों के बीच की जाती है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या यह अमीर राज्यों (उच्च औसत एमपीसीई वाले राज्य) में गरीब राज्यों

चार्ट 3: समय के साथ शहरी व्यय प्रीमियम

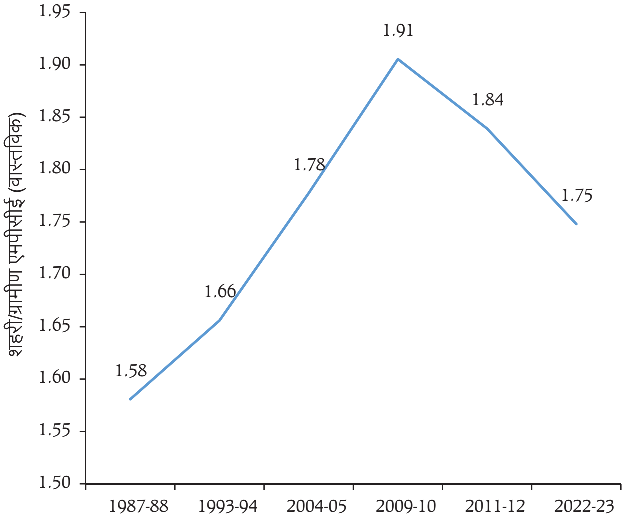

स्रोत: एनएसएसओ के विभिन्न दौर; और लेखकों के अनुमान।

चार्ट 4: शहरी व्यय प्रीमियम: 2011-12 बनाम 2022-23

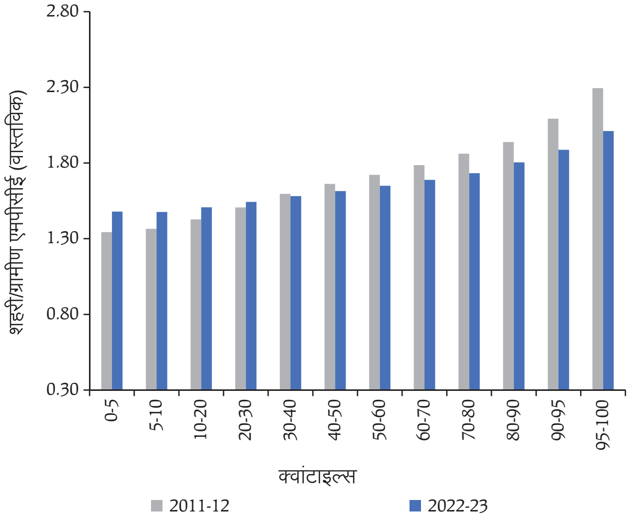

स्रोत: एनएसएसओ 2011-12 और 2022-23; तथा लेखकों के अनुमान।

की तुलना में कम है और क्या यह संबंध समय के साथ समान बना हुआ है। राज्यवार औसत एमपीसीई की गणना 2010-11 की जनगणना (सर्वेक्षण के लिए एनएसएसओ द्वारा इसी का उपयोग किया गया) से संबंधित शहरी और ग्रामीण आबादी के आधार पर किसी राज्य में औसत शहरी और ग्रामीण एमपीसीई को भारित करके की जाती है। 2011-12 और 2022-23 के लिए राज्यवार शहरी प्रीमियम और एमपीसीई के बीच संबंध की अलग-अलग जाँच की जाती है।

शहरी प्रीमियम का राज्यों के औसत एमपीसीई के साथ नकारात्मक संबंध है। इसका अर्थ है कि उच्च एमपीसीई वाले राज्यों में शहरी-ग्रामीण अंतर कम है (चार्ट 5)। हालाँकि, 2011-12 और 2022-23 के दौरान यह संबंध बदल गया है। स्कैटर प्लॉट में फिट की गई रेखाओं के ढलानों की तुलना करने पर, यह देखा गया है कि यह संबंध कमजोर हो गया है। ढलान में गिरावट मुख्य रूप से उन राज्यों में शहरी प्रीमियम में गिरावट के कारण है जिनका एमपीसीई राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। यह दर्शाता है कि 2011-12 और 2022-23 के बीच कम एमपीसीई वाले राज्यों में शहरी-ग्रामीण अंतर में काफी कमी आई है।

IV. राज्यों में अभिसरण

भारतीय संदर्भ में आर्थिक परिणामों में अंतर-राज्यीय असमानता और इसकी गतिशीलता पर साहित्य मुख्यतः भारतीय राज्यों के बीच प्रति व्यक्ति आय[2] में बढ़ते विचलन पर केंद्रित रहा है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानिक आर्थिक असमानता बढ़ रही

चार्ट 5: शहरी व्यय प्रीमियम और एमपीसीई के बीच संबंध, राज्य-वार: 2011-12 बनाम 2022-23

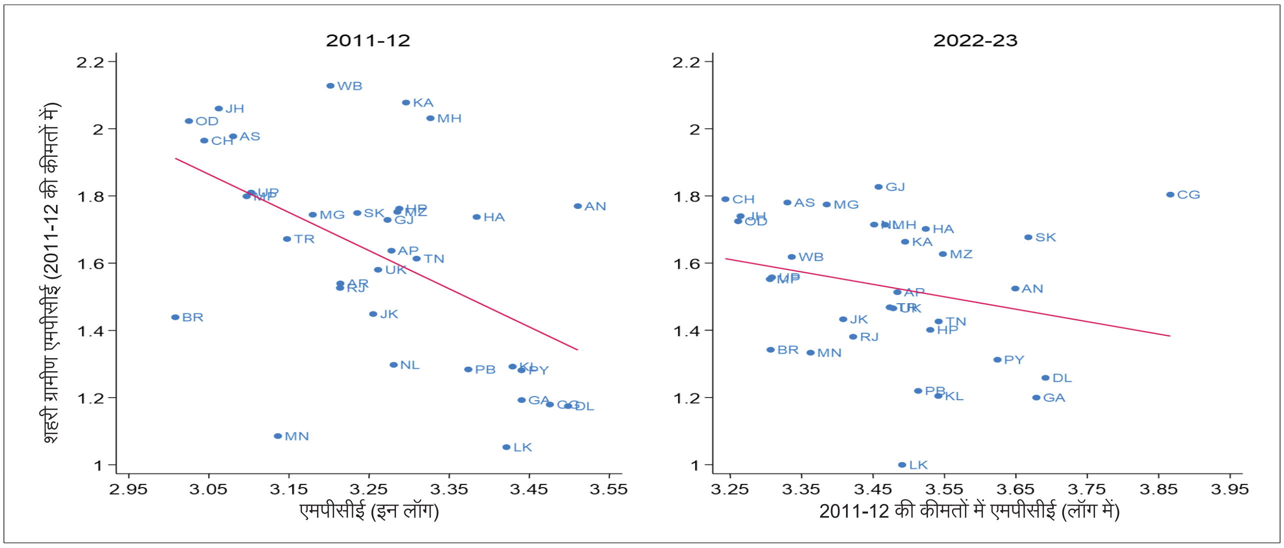

स्रोत: एनएसएसओ 2011-12 और 2022-23; तथा लेखकों के अनुमान।

2 राज्य स्तरीय प्रति व्यक्ति आय को राज्य स्तरीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का उपयोग करके मापा जाता है।

है। मोटे तौर पर, इन अध्ययनों से पता चला है कि हाल के दशकों में भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में बीटा-विचलन मौजूद है (घोष और कौस्तुभ, 2023; 2025)। भारतीय राज्यों के बीच एमपीसीई की गतिशीलता के संबंध में, आचार्य और अन्य., 2021 ने एनएसएसओ उपभोग व्यय सर्वेक्षणों के पहले के दौरों पर आधारित एक विस्तृत अध्ययन किया था और 1993-94 से 2011-12 के बीच की अवधि में राज्यों के बीच एमपीसीई में समग्र विचलन के प्रमाण पाए थे, और राज्यों को उनके जीवन स्तर के आधार पर समूहीकृत करने पर सशर्त अभिसरण के कुछ प्रमाण भी मिले थे। समाचार मीडिया में कुछ लेख नमूने (जैसे महाम्बारे और ज्योति, 2024) ने 2022-23 के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण दौर के संदर्भ में कुछ राज्यों में अलग-अलग प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/एनएसडीपी और अभिसरण एमपीसीई के बीच विरोधाभास के वास्तविक सबूत की ओर इशारा किया है। उदाहरण के लिए, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र में राजस्थान की तुलना में प्रति व्यक्ति एनएसडीपी अधिक है, ग्रामीण राजस्थान में एमपीसीई ग्रामीण गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में अधिक है। वे अनुमान लगाते हैं कि इस तरह के विरोधाभास को कई कारकों जैसे उच्च श्रम गतिशीलता जो श्रम-निर्यातक राज्यों में उनके जीएसडीपी स्तरों की तुलना में अधिक आय उत्पन्न करती है, और लोगों के जीवन स्तर पर बढ़ती स्थानिक आर्थिक असमानता के प्रभाव को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई सरकारी नीतियां और योजनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इस संदर्भ को देखते हुए, वर्तमान अध्ययन 2011-12 से 2022-23 की अवधि के बीच एमपीसीई की अंतर-राज्यीय गतिशीलता की जांच करता है। 2011-12 से 2022-23 की अवधि के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग, एक राज्य-स्तरीय बीटा-अभिसरण विश्लेषण किया जाता है। विशेष रूप से, बीटा-अभिसरण तब होता है जब कम प्रारंभिक मूल्यों वाले क्षेत्र अपने समृद्ध समकक्षों की तुलना में तेजी से विकास का अनुभव करते हैं। जैसा कि समीकरण 1 में दिखाया गया है, इस संबंध की जांच 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2011-12 में अपने एमपीसीई (लॉग(*एमपीसीई*)$_{i,2011-12}$) के लघुगणक पर i राज्य के 2011-12 और 2022-23 (Δ *वास्तविक एमपीसीई*) के बीच शहरी और ग्रामीण वास्तविक एमपीसीई में वृद्धि को प्रतिगमन करके की जाती है । मानक त्रुटियों (ei) को हेटेरोस्केडैस्टिसिटी के लिए मजबूत बनाया गया है। 2011-12 में एमपीसीई के लॉग का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण ऋणात्मक गुणांक (β) बिना शर्त बीटा-अभिसरण को दर्शाएगा और गुणांक का उच्च परिमाण अभिसरण की उच्च गति को दर्शाएगा (बैरो और साला-आई-मार्टिन, 1992; 1995)।

$$\Delta\ Real\ MPCE_i = \alpha + \beta * Log(MPCE)_{i,2011-12} + e_i \qquad (1)$$

उपरोक्त प्रतिगमन का परीक्षण करने पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 2011-12 में एमपीसीई में वृद्धि और एमपीसीई के लॉग के बीच एक महत्वपूर्ण ऋणात्मक संबंध प्राप्त होता है, जो राज्यों में प्रति व्यक्ति उपभोग में बीटा-अभिसरण को दर्शाता है (सारणी 1)। इसका तात्पर्य यह है कि 2011-12 में कम एमपीसीई वाले राज्यों ने तेजी से उपभोग वृद्धि का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 और 2022-23 के बीच उपभोग में अंतर-राज्यीय असमानता में कमी आई। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण की गति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जैसा कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए β के उच्च परिमाण से परिलक्षित होता है।

राज्यों में एमपीसीई में बीटा अभिसरण को बेहतर ढंग से देखने के लिए, 2011-12 के राज्यवार नाममात्र एमपीसीई (लॉग में) और 2011-12 से 2022-23 तक वास्तविक एमपीसीई में संबंधित वृद्धि के बीच एक स्कैटर आरेख ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्लॉट किया गया है (चार्ट 6)। बीटा अभिसरण के लिए, स्कैटर प्लॉट की फिट की गई रेखा का ढलान ऋणात्मक होना चाहिए, जैसा कि देखा गया है। काली ऊर्ध्वाधर धराशायी रेखा 2011-12 में राष्ट्रीय औसत एमपीसीई है। ऊर्ध्वाधर रेखा के बाई ओर के राज्यों का एमपीसीई 2011-12 में राष्ट्रीय औसत से कम था।

सारणी 1: बीटा-अभिसरण परीक्षण

चर	ग्रामीण	शहरी
β	-83.8***	-72.3*
α	333.6***	302.1**

नोट: *** 1 प्रतिशत महत्व स्तर को दर्शाता है, ** 5 प्रतिशत महत्व स्तर को दर्शाता है और * 10 प्रतिशत महत्व स्तर को दर्शाता है।

स्रोत: एचसीईएस 2011-12 और 2022-23 पर लेखक की गणना आधारित है।

चार्ट 6: राज्यों में वास्तविक एमपीसीई में अभिसरण

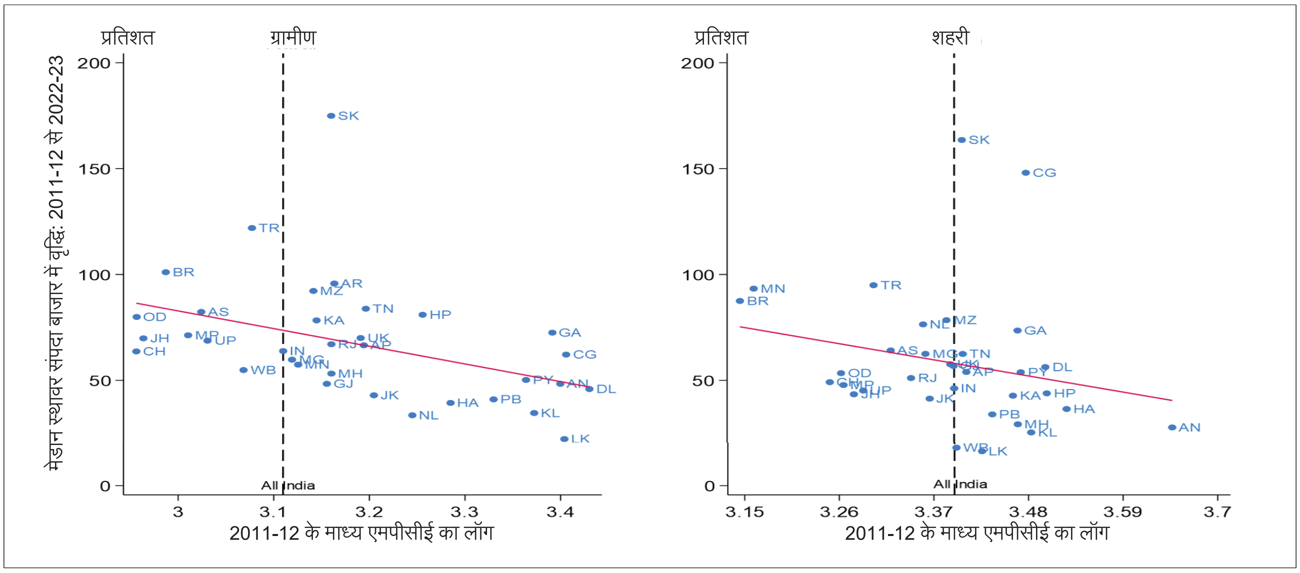

स्रोत: एनएसएसओ 2011-12 और 2022-23; तथा लेखकों के अनुमान।

ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का एमपीसीई राष्ट्रीय औसत से कम था और वे निर्धारित वक्र (लाल रेखा) से नीचे थे, जिसका अर्थ है कि इन राज्यों को अखिल भारतीय औसत एमपीसीई तक पहुँचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा क्योंकि उनकी वास्तविक एमपीसीई वृद्धि 2011-12 में उनके एमपीसीई के संबंध में अभिसरण अनुमान द्वारा सुझाए गए स्तर से नीचे थी। दूसरी ओर, अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) का एमपीसीई 2011-12 में राष्ट्रीय औसत से अधिक और निर्धारित रेखा से ऊपर था, जो यह दर्शाता है कि उनकी वास्तविक एमपीसीई वृद्धि अभिसरण अनुमान द्वारा सुझाए गए स्तर से ऊपर थी।

इस प्रकार, डेटा 2011-12 से 2023-24 की अवधि के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए राज्यों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में बिना शर्त बीटा-अभिसरण का प्रमाण दिखाता है। यह 1993-94 से 2011-12 के बीच की अवधि के लिए आचार्य और अन्य 2021 द्वारा प्राप्त परिणामों के विपरीत है। हालांकि, पहले के अध्ययन के निष्कर्षों के समान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और राज्यों के बीच अभिसरण की गति में विविधताएं हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में विचलन हो रहा है (घोष और कौस्तुभ, 2023; 2025), वहीं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एमपीसीई अभिसरण के संकेत दिखा रहा है। इससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में जीवन स्तर अधिक समान होता जा रहा है, भले ही उनका प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन अलग-अलग हो रहा है।

V. गरीबी रेखा का अनुमान लगाना

यह लेख गरीबी पर रंगराजन विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित पद्धति का अनुसरण करता है, जिसका गठन योजना आयोग ने 2011 में गरीबी के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया था। उपभोग-आधारित गरीबी रेखाएँ एक परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक बास्केट खरीदने के लिए आवश्यक धन की मात्रा निर्धारित करती हैं। घरेलू उपभोग व्यय पर सूक्ष्म-स्तरीय डेटा से गरीबी रेखा द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक खर्च करने वाले परिवारों का प्रतिशत पता चल सकता है। बढ़ती अर्थव्यवस्था में असमानता में कमी का अर्थ होगा कि गरीब परिवारों का खर्च अमीर परिवारों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। उपभोग व्यय के

अभिसरण में स्थानिक भिन्नता की सीमा तक, राज्यों में गरीबी में कमी में अंतर हो सकता है।

कुछ हालिया आलेखों ने एचसीईएस 2022-23 के उपभोग आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी के राज्यवार प्रभाव की गणना की है (भसीन और भल्ला, 2024; सेतु और अन्य., 2024)। उन्होंने कीमतों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए या तो विश्व बैंक की क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) गरीबी रेखाओं $1.9 और $3.2 का उपयोग किया है या घरेलू गरीबी रेखाओं (तेंदुलकर समिति या रंगराजन समिति द्वारा सुझाई गई) को सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ बढ़ाकर दर्शाया है। हालाँकि, इन दृष्टिकोणों के साथ समस्याएँ हैं। विश्व बैंक की गरीबी रेखाओं, जिन्हें डॉलर में परिभाषित किया गया है, को रुपये में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक पीपीपी परिवर्तन कारक के संबंध में आम सहमति का अभाव है। रंगराजन या तेंदुलकर गरीबी रेखा को मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति के साथ बढ़ाने के लिए, सीपीआई बास्केट में उपभोग वस्तुओं का भार गरीबी रेखा बास्केट (पीएलबी) में उन वस्तुओं के भार से बहुत भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रंगराजन पीएलबी में खाद्य पदार्थों का भार 57 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण सीपीआई उपभोग बास्केट में इसका भार 54 प्रतिशत है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों के लिए रंगराजन पीएलबी में खाद्य पदार्थों का भार 47 प्रतिशत है, जबकि शहरी सीपीआई उपभोग बास्केट में इसका भार 36 प्रतिशत है। इस प्रकार, पीएलबी में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति उपयुक्त मीट्रिक नहीं हो सकती है।

इससे निपटने के लिए, सीपीआई बास्केट से आइटम भार का उपयोग करने के बजाय, रंगराजन पीएलबी में प्रत्येक आइटम के भार के आधार पर एक मूल्य सूचकांक विकसित किया गया है। इस अवधि के दौरान पीएलबी के लिए मुद्रास्फीति निर्धारित करने के लिए पीएलबी में संबंधित आइटम के भार द्वारा इन परिवर्तनों को समायोजित करते हुए, 2011-12 और 2022-23 के बीच प्रत्येक आइटम के मूल्य परिवर्तनों की गणना की जाती है। यह विश्लेषण प्रत्येक राज्य में शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए अलग-अलग किया गया था। इसके बाद, रंगराजन समिति की नाममात्र गरीबी रेखाओं को, 2012 की गरीबी रेखा से पिछले चरण में की गई चर्चा के अनुसार मुद्रास्फीति दरों के साथ समायोजित करके अद्यतन किया गया। अंत में, एचसीईएस 2022-23 के सूक्ष्म-आँकड़ों का उपयोग करके प्रत्येक राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अद्यतन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत प्राप्त किया गया।

2014 में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाली रंगराजन समिति, द्वारा सुझाई गई पद्धति में तेंदुलकर समिति द्वारा निर्मित पिछली आधिकारिक गरीबी रेखा की तुलना में कुछ विशिष्ट लाभ थे। पहला, रंगराजन समिति की कार्यप्रणाली शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए दोनों समूहों के बीच उपभोग पैटर्न में अंतर के आधार पर अलग-अलग पीएलबी परिभाषित करती है। दूसरा, तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली द्वारा गरीबी रेखा को न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं से अलग करने के बाद, कार्यप्रणाली उन्हें फिर से जोड़ती है। तीसरा, रंगराजन समिति की रिपोर्ट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएलबी में प्रत्येक मद का भारांक देती है, जिससे प्रत्येक राज्य के लिए 2022-23 की कीमतों में इन श्रेणियों के नाममात्र मूल्य की गणना करना संभव हो जाता है।[3]

सारणी 2 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट में बताई गई 2011-12 की राज्यवार गरीबी रेखा और 2022-23 की गरीबी रेखा शामिल है, जिसका अनुमान बड़े भारतीय राज्यों के लिए ऊपर वर्णित कार्यप्रणाली का उपयोग करके लगाया गया है।

एचसीईएस 2022-23 के सूक्ष्म-आँकड़ों का उपयोग करके, 2022-23 में प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के प्रतिशत की गणना की गई। इन्हें 2014 की रंगराजन रिपोर्ट से क्रमशः 2009-10 और 2011-12 में राज्यों के गरीबी प्रतिशत के साथ सारणी 3 में दर्शाया गया है। एचसीईएस 2011-12 की तुलना में एचसीईएस 2022-23 में प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी की घटनाओं में पर्याप्त कमी देखी गई है। एचसीईएस 2022-23 का उपयोग करने वाले अन्य अध्ययनों ने भी इस अवधि के दौरान गरीबी में पर्याप्त गिरावट पाई है,

[3] यह ध्यान देने योग्य है कि इस आलेख में अनुमानित गरीबी रेखा 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित पद्धति पर आधारित है। रिपोर्ट जारी हुए दस साल बीत चुके हैं, और उपभोग के पैटर्न में बदलाव आया है और उपभोग की बास्केट में नई वस्तुएँ अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसके लिए एक नई गरीबी रेखा का निर्माण आवश्यक हो सकता है जो वर्तमान वास्तविकता को बेहतर ढंग से दर्शा सके (भसीन और भल्ला, 2024; देव और अन्य., 2024)।

सारणी 2: रंगराजन पद्धति का उपयोग करते हुए राज्यवार गरीबी रेखा 2011-12 और 2022-23

(रुपये में)

राज्य	ग्रामीण 2011-12	शहरी 2011-12	ग्रामीण 2022-23	शहरी 2022-23
आंध्र प्रदेश	1032	1371	1903	2588
असम	1067	1420	1968	2586
बिहार	971	1229	1724	2277
छत्तीसगढ़	912	1230	1586	2149
दिल्ली	1492	1538	2577	2592
गुजरात	1103	1507	2014	2664
हरियाणा	1128	1528	2083	2696
हिमाचल प्रदेश	1067	1412	1895	2547
जम्मू और कश्मीर	1044	1403	1980	2653
झारखंड	904	1272	1621	2356
कर्नाटक	975	1373	1784	2599
केरल	1054	1354	1982	2563
मध्य प्रदेश	942	1340	1707	2521
महाराष्ट्र	1078	1560	2006	2791
ओडिशा	876	1205	1608	2182
पंजाब	1127	1479	2048	2622
राजस्थान	1036	1406	1887	2561
तमिलनाडु	1082	1380	2041	2608
उत्तर प्रदेश	890	1330	1622	2429
पश्चिम बंगाल	934	1373	1755	2572

नोट: तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल है; लद्दाख जम्मू और कश्मीर में शामिल है।

स्रोत: एचसीईएस 2022-23; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एमओएसपीआई; और लेखकों की गणना।

सारणी 3: चुनिंदा भारतीय राज्यों में 2009-10, 2010-11 और 2022-23 में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत

राज्य	ग्रामीण 2009-10	शहरी 2009-10	ग्रामीण 2011-12	शहरी 2011-12	ग्रामीण 2022-23	शहरी 2022-23
आंध्र प्रदेश	27.0	30.5	12.7	15.6	1.2	2.2
असम	42.9	40.2	42.0	34.2	8.7	5.5
बिहार	65.1	55.0	40.1	50.8	5.9	9.1
छत्तीसगढ़	58.9	36.5	49.2	43.7	25.1	13.3
दिल्ली	4.9	24.7	11.9	15.7	0.9	2.6
गुजरात	37.0	35.6	31.4	22.2	5.9	4.1
हरियाणा	19.2	24.8	11.0	15.3	4.1	4.3
हिमाचल प्रदेश	11.2	22.5	11.1	8.8	0.4	2.0
जम्मू और कश्मीर	14.4	32.4	12.6	21.6	4.2	4.1
झारखंड	55.3	42.1	45.9	31.3	16.6	12.6
कर्नाटक	24.3	26.7	19.8	25.1	0.9	3.3
केरल	9.7	23.7	7.3	15.3	1.4	4.3
मध्य प्रदेश	51.3	45.0	45.2	42.1	9.6	11.6
महाराष्ट्र	27.6	30.3	22.5	17.0	11.3	8.6
ओडिशा	50.0	41.2	47.8	36.3	8.6	10.2
पंजाब	14.8	28.6	7.4	17.6	0.6	2.6
राजस्थान	31.9	38.5	21.4	22.5	6.8	6.7
तमिलनाडु	25.9	29.7	24.3	20.3	2.1	1.9
उत्तर प्रदेश	46.3	49.6	38.1	45.7	5.7	9.9
पश्चिम बंगाल	37.8	36.6	30.1	29.0	7.5	12.4

नोट: आंध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल है; जम्मू और कश्मीर में लद्दाख शामिल है।

स्रोत: एचसीईएस 2022-23, और लेखक की गणना।

हालांकि उनके द्वारा गणना की गई गरीबी दर इस अध्ययन के अनुमानों से अलग है, यह कार्यप्रणाली में अंतर के कारण है। भसीन और भल्ला, 2024 के पेपर ने 2022-23 में कुल गरीबी हेडकाउंट अनुपात दर 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था जो 2011-12 में 12.2 था। उनके द्वारा अनुमानित गरीबी रेखा विश्व बैंक के 1.99 अमरीकी डॉलर प्रति दिन के उपभोग व्यय के माप पर आधारित है जिसे वे क्रय शक्ति समता माप का उपयोग करके रुपये में परिवर्तित करते हैं। सेतु और अन्य., 2024 ने भी एचसीईएस 2022-23 का उपयोग करते हुए गरीबी के प्रभाव का अनुमान लगाया और पाया कि पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 23 प्रतिशत और 27.4 प्रतिशत गरीबी दर है। उनकी गरीबी दर उनके द्वारा निर्मित गरीबी रेखा पर आधारित है, जिसमें परिवार के सदस्यों के व्यवसाय और आयु के आधार पर उनकी अद्यतन कैलोरी संबंधी ज़रूरतें शामिल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान अध्ययन किसी गरीबी रेखा का निर्माण नहीं करता है, बल्कि मद-वार मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके रंगराजन गरीबी रेखा को अद्यतन करता है।

निष्कर्ष

यह अध्ययन एनएसएसओ द्वारा 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के उपभोग व्यय आंकड़ों की तुलना 2011-12 में किए गए सर्वेक्षण से करता है, जो व्यय वर्गों, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों और राज्यों जैसे विभिन्न आयामों में अभिसरण पर केंद्रित है। परिणाम दर्शाते हैं कि एमपीसीई में अभिसरण की एक व्यापक प्रवृत्ति है। गहन विश्लेषण से पता चलता है कि व्यापक प्रवृत्ति के कुछ अपवाद भी हैं। व्यय दशमलवों और क्षेत्रों में उपभोग

व्यय में असमानता में कमी को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समझाया जा सकता है। साथ ही, अध्ययन ने रंगराजन समिति की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इन आंकड़ों के साथ प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी रेखा का पुनर्मूल्यांकन किया। गरीबी की अनुमानित घटना भारत के राज्यों में गरीबी में समग्र कमी दर्शाती है।

संदर्भ

Acharya, D., Rath, B.N., Parida, T.K. (2021). Convergence in Monthly Per Capita Expenditure and the Rural–Urban Dichotomy: Evidence from Major Indian States. In: Batabyal, A.A., Higano, Y., Nijkamp, P. (eds) Rural–Urban Dichotomies and Spatial Development in Asia. New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, vol 48. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1232-9_10

Barro, R. J. and Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2), 223-251.

Barro, R. J. and Sala-i-Martin, X. (1995). *Economic Growth*. London. McGraw-Hill.

Bhasin, Karan and Bhalla, Surjit (2024). Poverty in India over the last decade. *Economic and Political Weekly*.

Bonu, S. (2024, August 22). Consumption Expenditure by Social Groups: Findings from India's Household Consumption Expenditure Survey, 2022-23. Isaac Centre for Public Policy, Ashoka University.

Chanda, A., and Cook, J. C. (2022). Was India's demonetization redistributive? Insights from satellites and surveys. *Journal of Macroeconomics*.

Dev, M. and Rangarajan, C. (2024, March 12). With new consumption survey, the need for new indices, *Indian Express*.

Ghosh, S. (2024, January 15). India's K-shaped recovery debate has economists divided. *Mint*.

Ghosh, T. and Kaustubh. (2023). Growth decomposition of the Indian states using panel data techniques. *Applied Economics*, 56(39), 4664–4684.

Ghosh, T., and Kaustubh. (2025). Growth Divergence between Indian States. Economic and Political Weekly, 60(6)

Gupta, A., Malani, A., and Woda, B. (2021). Inequality in India declined during covid. *NBER Working Paper*.

Himanshu. (2017, November 6). Demonetisation, inequality and informal sector. *Mint*.

Iyer, Vaidyanathan P. (2024, February 26). Five questions the Household Consumption Expenditure Survey 2022-23 answers. *The Indian Express*.

Jha, M., and Lahoti, R. (2022). Who was impacted and how? COVID-19 pandemic and the long uneven recovery in India. *WIDER Working Paper*.

Mahambare, Vidya and Jyoti, Amar. (2024, March 19) What tells us more about prosperity: Consumption or GDP per head? *Mint*.

Mitra, A., & Shrivastav, P. K. (2024). Interstate inequality in consumption: Emerging evidence from HCES 2022–23. *Economic & Political Weekly*, 59(28), 17–20.

Nageswaran, V. A., Guru, Anuradha and Bisht, D. S. (2024, March 6). India's consumption numbers fit into our big picture of progress. *Mint*.

Rampal, Nikhil (2024, February 27). Here are 5 key takeaways from Household Consumption Expenditure Survey 2022-2023. *The Print*.

Sethu, C. A., Abhinav Surya, L. T. and Ruthu, C. A. (2024), Poverty in India: The Rangarajan Method and the 2022–23 Household Consumption and Expenditure Survey. *Review of Agrarian Studies*, 14(2).